भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2428
उत्तर देने की तारीख 18 दिसंबर, 2023
सोमवार, 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

कौशल उन्नयन योजना हेतु अन्य देशों के साथ भागीदारी

2428. श्री रवनीत सिंहः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कौशल उन्नयन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता वाले विश्व के अन्य देशों के साथ भागीदारी करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्योरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को होने वाले संभावित लाभों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उदयमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क), (ख) और (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य देश के युवाओं को भावी और उद्योग हेतु कौशल के लिए सक्षम बनाना है।
एमएसडीई का प्रयास विभिन्न देशों के साथ जुड़ना और देश के युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। एमएसडीई के तत्वावधान में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने उनकी कौशल आवश्यकताओं को समझने के लिए निम्नलिखित 16 देशों: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम का अध्ययन किया है।

इसके अलावा, एमएसडीई ने 11 देशों के साथ गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 08 समझौता ज्ञापन वर्तमान में विभिन्न देशों अर्थात्: ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, यूएई और यूके के साथ कार्यात्मक हैं। समझौता ज्ञापन कौशल तालमेल के लिए सूचना विनिमय, मानक निर्धारण, अर्हताओं की पारस्परिक

मान्यता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षुता आदि जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में भागीदार देश के साथ सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, एमएसडीई के पास आठ (08) देशों के साथ सक्रिय गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट समझौता ज्ञापन अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, यूएई और यूके हैं। इसे समझौता ज्ञापन कुशल गतिशीलता के लिए सूचना विनिमय, मानक निर्धारण, अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, इंटर्नशिप आदि जैसे क्षेत्रों में भागीदार देश के साथ सहयोग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एनएसडीसी (एनएसडीसी-I) ने भारतीय कुशल कार्यबल की विदेशी गतिशीलता, प्रशिक्षकों की क्षमता-निर्माण, नियोक्ता की भागीदारी आदि की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की व्यावसायिक संस्थाओं के साथ बिजनेस-टू-बिजनेस समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय-वर्ष 2023-24 के लिए बजट घोषणा के अनुरूप, एमएसडीई ने विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। एसआईआईसी के स्थानों का चयन देश और क्षेत्र-वार प्रवासन पैटर्न, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी गतिशीलता की मांग और अन्य व्यवहार्यता मापदंडों पर आधारित है। एसआईआईसी की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। ये केंद्र गंतव्य-आधारित कौशल/पुनर्कौशल/कौशलोन्नयन सुविधा, नियोजन में सहायता, परामर्श, आकलन/ट्रेड परीक्षण, उत्प्रवास सहायता और नियोजन पश्चात सहायता प्रदान करके युवाओं को कुशल गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेंगे।

वर्तमान में, दो एसआईआईसी एक वाराणसी में और दूसरा एसडीआई, भुवनेश्वर में स्थापित किए गए हैं।

एमएसडीई के प्रयासों के परिणामस्वरूप, अप्रैल, 2022 और दिसंबर, 2023 के बीच कुल 25,300 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक विदेश में रोजगार प्राप्त किया है। देश-वार विवरण **अनुबंध** में हैं।

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुबंध।

तालिका I: विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की देश-वार संख्या:

क्र.सं.	**देशों के नाम**	**उम्मीदवारों की संख्या**
1.	ऑस्ट्रेलिया	2
2.	बहरीन	935
3.	क्रोएशिया	4
4.	जापान	1196
5.	सऊदी अरब किंग्डम	13944
6.	कुवैत	399
7.	ओमान	1094
8.	कतर	3646
9.	संयुक्त अरब अमीरात	2832
10.	यूनाइटेड किंगडम	1248
	सकल योग	**25,300**

*****